[श्रीमती सुषमा स्वराज]

कहना चाहूंगी कि इस तरह की बातों की भर्त्सना पूरे सदन को करनी चाहिए । अब वह समय आ गया है जब इस तरह के निर्देश देने चाहिए कि दूरदर्शन इस तरह का व्यवहार सारणी आचरण बंद करे वरना इस देश के प्रजातंत्र पर एक सवालिया निशान लग जायेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी0के0 थुंगन) : आप भी अगर अच्छा काम करेंगी तो आपको भी दिखायेंगे ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर सच होता तो मैं रीयअली मान लेती कि बिल्कुल दिखाना चाहिए । आप अपनी आत्मा पर हाथ रख कर बताईये कि झुग्गी-झोंपडी वालों का स्तर क्या एक कार तक पहुंचा दिया है ?

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश) **:** उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ रही है और जहां कांग्रेस की सरकार है कि ओर आकर्षित करना चाहता हूं । एक ओर जहां भारत सरकार की नाक के नीचे एक महिला का शव तंदूर में जलाया जाता है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्वांचल में महिलओं और बच्चों का अपहरण करके उनको अनैतिक कामों के लिए बम्बई में बेचे जाने की जानकारी मिली है । इस आश्य का समाचार 21 जुलाई के नयी दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ है । इसके मुताबिक मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल से नौ महिलाओं का अपहरण कर उन्हें बंबई के चकलाघरों में बेचे जाने का पता चला है । इसमें महिलाओं की जो कीमत लगती है वह इस प्रकार है । जो महिला बिना बच्चे की है उसकी कीमत 10 हजार रुपये तक मिल जाती है और अगर एक बच्चे की मां है तो उसके 3 से 5 हजार रुपये तक में बेचा जाता है और उसके जो बच्चे होते है उनको भी बेच दिया जाता है । अगर लड़की हुए तो उसके दाम ज्यादा मिलते हैं । ये लोग रेलों में यात्री के रूप में यात्रा करते है और महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करते है और फिर उन्हें बम्बई ले जाकर चकलाघरों में बेच देते है । एक महिला किसी तरह से उनके चंगुल से निकल कर भागी और उसने बताया कि दुर्ग रेलवे स्टेशन पर चाय पिलाकर बेहोश कर बंबई में उसे 3200 रुपये में बेचा गया था । वहां से किसी तरह वह भागकर आयी

और पुलिस में रिपोर्ट की । पता चला है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर बिलासपुर आदि जगहों से इन लोगों ने नौ महिलाओं का अपहरण कर उन्हें बंबई के चकलाघरों में बेचा है । इनमें अभी तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है । इनमें एक महिला है जिसका नाम आशा है और दो अन्य अभियुक्त अनवर और उत्तमदास है । महोदया, इसमें और बडी गिरफतारियां होने की संभावना है । यह देखा गया है कि जो इन धंधों में लिप्त होते है वे बिना बड़े लोगो की मदद से ऐसा नहीं कर सकते । लेकिन छोटे अपराधी तो गिरफतार हो जाते हैं और बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है जैसा यहां तंदूर कांड में हुआ है । कुछ छोटे लोगों को गिरफतार किया गया है लेकिन जो बड़े बड़े लोग इसमें हैं उनको छोड़ दिया गया है ।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह) : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिक्री का केन्द्र बंबई है ना ?

श्री गोविन्दराम मिरी : बम्बई है ।

श्री राम लखन सिंह यादव : वहां की सरकार क्या कर रही है । इसको रोकने के लिए उसने क्या किया?

श्री गोविन्दराम मिरी : आप अभी कांग्रेस मे नये नये आए हैं । कांग्रेस कल्चर में आप पूरी तरह शामिल नहीं हो पाए है ।

श्री राम लखन सिंह यादव : कांग्रेस की बात मत कीजिए । मैं जन्म से ही कांग्रेस में रहा हूं ।

श्री गोविन्दराम मिरी : यह मध्य प्रदेश में हो रहा हैं, जहां आपकी सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां की मैं बात कह रहा हूं ।

श्री राम लखन सिंह यादव : लेकिन बंबई में बेच रहे हैं आपने कहा है ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) **:** यह सब मध्य प्रदेश में हुआ है, जहां आपकी सरकार है ।

श्री गोविन्दराम मिरी : मैं यह जानना चाहता हूं और हमारे यहां कहा जाता है कि "यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते तत्र रमंते देव

वहां यह स्थिति हो गई है । यहां महिलायें सुरक्षित है । कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगडी हुई है । हम यहां पर बड़े बड़े दम भरते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे । लेकिन आये दिन इस तरह की घटनायें हो रही हैं । मैं सदन के माध्यम से केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की पूरी जांच कराये और

जो लोग इसके दोषी पाए जाएं उनको कड़े से कड़ा दंड दें और जो महिलाओं और बच्चों का अपहरण करके अनैतिक कार्य किया जा रहा है सरकार इसको रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे।

Clearance of Irrigation Schemes and Release of Forest land for Kali-II Irrigation Scheme in Gujarat

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Madam, with this Special Mention, I want to request the Ministry of Water Resources and the Ministry of Environment and Forests to clear toe two pending projects in the Panchmahal District of Gujarat State. They are Goma Irrigation Scheme and the other one is Kali-II Irrigation Scheme. Goma Irrigation Scheme is proposed in Kaiol Taluka of Panchmahal District for which the Gujarat Government has accorded the revised administrative approval for Rs. 3,115 lakhs on 19.7.91. *The* project will provide the irrigation facilities in 4,804 hactares of land including 334 hectares of land of Central Horticultural Research Station. The project was under correspondence with CWC and the last letter was responded to by the Gujarat Government on 16.6.95 and the clearance is awaited. I may also state that the Government of India has agreed to diversion of 172.35 hectares of forest land for which the State Government has already paid Rs. 51.19 lakhs to the Forest Department towards the cost of compensatory afforestation. Also, 132 hectares of non-forest land has been transferred to the Forest Department, and the rest of the 40 hectares of land is likely to be transferred by this month. The rehabilitation and settlement plan has also been approved and the Planning Commission has agreed to include the scheme in the remaining period of the 8th Plan with the provision of Rs. 400 lakhs. This is being delayed for want of TAC clearance.

Madam, the Kali-II Irrigation Scheme is proposed in the Adivasi and remote area of Zalod Taluka, District Panchmahal in Gujarat. This scheme was approved by the Gujarat Government in the year 1985. The scheme is to cost Rs. 615.20 lakhs and it will provide irrigation facilities to 1,515 hectares of land in ll villages of the tribal area of Zalod Taluka. The Gujarat Government has already provided the budgetary amount of Rs. 50 lakhs for this minor irrigation this year, but the question of 102 hectares of forest land to be released by the Forest Department was involved, to which the State Government has agreed. But the order from the Government of India is awaited, and the poor Adivasis are being deprived of irrigation.

Therefore, I request the Minister of Water Resources and the Ministry of Environment and Forests to expedite both these schemes. Thank you, Madam.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE (Gujarat): I fully associate myself with this. So many projects of the Gujarat Government are pending with the Forest Department and the Environment Department since very long. These should be cleared as early as possible because the drinking water shortage is very accute in Gujarat, particularly in the Adivasi districts. So, please do something. I request the Government to take necessary action.

Need for legislation of 30 percent reservation of seats for women in Parliament and Assemblies

SHRIMATI CHANDRIKA ABHI-N AND AN JAIN (Maharashtra): Madam, criminalisation of politics has reached its zenith. In fact, I should say that it has reached its nadir in recent times with the mafia having its stranglehold over the politics and the economy in our country. All parties are to be blamed. We cannot just pinpoint one particular personality or one party and say that this particular party has been encouraging the nexus between politicians and criminals. I remember, in 1986 when I was the Minister of Education and Law in the